साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 10 मई 2021, वर्ष-7, अंक-06

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8,मूल्य :- 8 रुपए

मध्यप्रदेश में कृषि विभाग 15 जून के बाद बांटेगा 20 लाख मिनी किट

किसानों को मुफ्त में मिलेगा अरहर, उड़द और मूंग का बीज

संवाददाता, भोपाल

अरहर, उड़द और मूंग समेत दूसरे दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इस बार खरीफ के सीजन में किसानों को 82 करोड़ से ज्यादा की 20 लाख बीज की किट मुफ्त देगा। कृषि मंत्रालय ने खरीफ 2021 सत्र में दलहन के उत्पादन और रकबा बढ़ाने के लिए विशेष खरीफ रणनीति तैयार की है। आगामी खरीफ सीजन 2021 में मंत्रालय 20,27,318 बीज किट वितरित करेगा। साल 2020-21 की तुलना में लगभग ये लगभग 10 गुनी होगी। इन मिनी बीज किट्स का मूल्य लगभग 82.01 करोड़ है। अरहर, मूंग और उड़द के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इन मिनी किट्स की कुल लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। मंत्रालय के बयान के मुताबिक केंद्र सरकार के इस प्रयास से पूरे देश में लगभग 4.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर होगा। वर्ष 2007-08 की तुलना में वषज़ 2020-21 में दालों का उत्पादन 65 प्रतिशत बढ़ गया है।

मप्र में भी होगा वितरण

मप्र के किसानों को भी कृषि विभाग द्वारा मुफ्त में बीजों का वितरण किया जाएगा। यह वितरण 15 जून तक शुरू कर दिया जाएगा। वहीं दतिया कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक पुनीत राठौर का कहना है कि अभी हमें इस संदभज़ में कोई जानकारी नहीं मिली है। हां यह जरूर है कि सोशल मीडिया पर मंत्रालय का पत्र देखा है। जैसे ही हमें बीजों की किट मिल जाएगी वैसे ही उसका वितरण शुरू कर दिया जाएगा।

इन राज्यों में दी जाएंगी किट

अरहर को एक से अधिक फसल के लिए 11 राज्यों और 187 जिलों में कवर किया जाएगा। ये राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कनाज़्टक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।

छह राज्यों का उड़द

छह छह राज्यों और 60 जिलों में उड़द इंटरक्रॉपिंग को कवर किया जाएगा। ये राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कनाज़्टक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं। उड़द को एकमात्र फसल के रूप में 6 राज्यों में शामिल किया जाएगा।

निःशुल्क होगा वितरण

कृषि मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ परामशज़ के माध्यम से, अरहर, मूंग और उड़द की बोवनी के लिए रकबा बढ़ाने और उत्पादकता बढ़ाने दोनों के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। रणनीति के तहत, सभी उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों का उपयोग करना शामिल है। केंद्रीय बीज एजेंसियों या राज्यों में उपलब्ध यह उच्च उपज की किस्म वाले बीज, एक से अधिक फसल और एकल फसल के माध्यम से बोवनी का रकबा बढ़ाने वाले क्षेत्र में निःशुल्क वितरित किए जाएंगे।

गेहूं खरीदी में होशंगाबाद अव्वल

समर्थन मूल्यः उज्जैन दूसरे और विदिशा तीसरे नंबर पर

- 56 हजार किसानों से छह लाख मीट्रिक गेहूं खरीदा
- प्रदेश सरकार ने अब तक खरीदा 10,600 करोड़ का 53 लाख टन गेहूं
- कोरोना के चलते खरीद की गति धीमी पर खरीद जारी रखने के दिए निर्देश
- खरीदी केंद्रों पर बड़ी लापरवाही, गेहूं गोदाम तक पहुंचाने की व्यवस्था ठप
- बारिश में गेहूं की बोरियों को ढंक तक नहीं पाए और नुकसान मप्र सरकार का होगा

अरविंद मिश्र, भोपाल

प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच वर्ष 2020-21 समर्थन मूल्य पर जारी गेहूं खरीदी में हर बार ही तरह इस बार भी नर्मदापुरम (होशंगाबाद) मप्र के सबसे आगे स्थान पर है। 56 हजार किसानों से 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद चुका है। इन्हें 641 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो चुका है। दूसरे नंबर पर उज्जैन और तीसरे पर विदिशा जिला है। उज्जैन में 5.89 लाख मीट्रिक व विदिशा में 5.16 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। वहीं प्रदेश भर में सरकार ने अभी तक 53.69 लाख टन से ज्यादा गेहूं खरीदा है। इस गेहूं की खरीद की कीमत 10,600 करोड़ रुपए है। इसमें से छह हजार करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। कोरोना के चलते खरीद की गति धीमी हुई है, लेकिन कोरोना गाइड-लाइन का पालन करते हुए खरीद जारी रखने के निदेज़्श दिए गए हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष प्रदेश सरकार ने एक करोड़ 29 लाख टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की थी।

हरदा-बैतूल की स्थितिः नर्मदापुरम संभाग के हरदा में 112 केंद्रों पर खरीदी जारी है। 25040 किसानों से 2.23 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। इसके एवज में 261 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। वहीं, बैतूल में 92 केंद्रों पर 13691 किसानों से 74803 मीट्रिक टन गेहूं खरीद चुके। 66 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है।

किसानों की संख्या

55763	होशंगाबाद
59240	सीहोर
82232	उज्जैन
82232	उज्जैन
49507	रायसेन
51084	विदिशा
30854	जबलपुर

गेहूं खरीदी में टॉप पांच जिले

जिला	गेहूं खरीदी मीट्रिक टन	भुगतान करोड़ रु.
होशंगाबाद	600136	641.25
उज्जैन	589929	657.97
विदिशा	516381	661.14
सीहोर	488889	547.23
रायसेन	465382	513.68
जबलपुर	350704	363.79

इनका कहना है

अब तक प्रदेश में सात लाख 32 हजार पंजीकृत किसानों से 10 हजार 600 करोड़ राशि के 53 लाख 69 हजार मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। चार हजार 588 उपार्जन केंद्रों से उपार्जन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। गेहूं को बारिश से बचाने के लिए तिरपाल के भी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। किसान चिंता न करें।

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

दतिया जिले के 80 केंद्रों पर परिवहन के लिए गेहूं रखा है। समय सीमा में गेहूं परिवहन नहीं होने से परिवहनकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। बारिश से केंद्रों पर पड़ा गेहूं भीगा होगा। बारिश से गेहूं खराब होने की संभावना उत्पन्न हुई है। अगर गेहूं खराब होता है तो परिवहनकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

डीएस धाकरे, सहायक जिला खाद्य अधिकारी, दतिया

सभी खरीदी केंद्रों पर गेहूं खरीदी का कार्य लगातार तेजी से जारी है। खरीदी के साथ ही परिवहन भी किया जा रहा है। केंद्र अधिक कर दिए गए हैं। हर केंद्र से उठाव हो रहा है। जल्द ही परिवहन की समस्या पूरी हो जाएगी। हल्की बारिश हुई है उससे गेहूं नहीं भीगा है।

दिलीप सक्सेना, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति अधिकारी, होशंगाबाद

होशंगाबाद में एक अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य 244 केंद्रों पर जारी है। 34 दिनों में किसानों से गेहूं खरीदी कर हमारा जिला प्रदेश में टाप स्थान पर पहुंच गया है। जिले ने बहुत कम समय में रिकॉर्ड खरीदी की है। संपूर्ण मप्र के होशंगाबाद जिला किसानों से सबसे अधिक गेहूं खरीदी में किए जाने में प्रथम स्थान पर है।

अनिल तंतुवाय, सहायक जिला आपूर्ति नियंत्रक

प्रदेश में बारिश से लाखों मीट्रिक टन गेहूं भीगा

कोरोना काल के बीच प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम के करवट लेते ही अन्नदाता के माथे पर फिर चिंता की लकीरें उभर आईं। अन्नदाता के माथे पर चिंता की लकीरें इसलिए हैं, क्योंकि प्रदेशभर में हजारों उपाजज़्न केंद्रों पर गेहूं खरीदी का कार्य चल रहा है। लेकिन नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा खरीदी केंद्रों से कराया जा रहा गेहूं परिवहन व्यवस्था लचर है। केंद्रों पर गेहूं का परिवहन समय पर नहीं होने से लाखों मीट्रिक टन गेहूं बारिश से भीग गया है। वहीं सिर्फ दतिया में ही गेहूं का परिवहन नहीं होने से 25 हजार मीट्रिक टन गेहूं भीग गया है। अगर गेहूं का रखरखाव नहीं किया गया तो यह खराब हो जाएगा।

कहां-कहां भीगा गेहूं

बेमौसम बारिश होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, शिवपुरी, दतिया, मुरैना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट सहित अन्य कुछ जिलों में भी बारिश गेहूं भीगने की जानकारी मिली है।

हर केंद्र पर खुले में पड़ा गेहूं

कृषि उपज मंडी का केंद्र हो या फिर किसी गांव में खेत में बने हुए खरीदी केंद्र हो सभी जगह पर हजारों क्विंटल गेहूं खुले में पड़ा हुआ है। आवक अधिक और परिवहन कम होने के कारण सभी केंद्रों पर गेहूं का अंबार लगता जा रहा है। यही स्थिति रही तो एक दो दिन में खरीदी बंद कर परिवहन करना पड़ेगा क्योंकि बार-बार बारिश हो रही है।

कृषि अधोसंरचना विस्तार की कवायद में सरकार

2022 तक किसानों की आय दो गुना करने का लक्ष्य

फंड में 7 हजार करोड़ रुपए का किया जाएगा प्रावधान

मध्यप्रदेश में अब स्थापित होगा कृषि अधोसंरचना फंड

किसानों को मिलेगा सस्ता कर्ज

संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश में केंद्र के साथ ही शिवराज सरकार का भी कृषि अधोसंरचना के क्षेत्र विकास पर पूरा फोकस है। मप्र सरकार ने किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि मध्यप्रदेश में वैसे तो किसानों को खेती के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज पर कर्ज मिल रहा है, लेकिन अब खेती से जुड़े व्यवसाय के लिए भी उन्हें सस्ता कर्ज मुहैया कराने की योजना बनाई गई है। यानी अब उन्हें तीन फीसदी तक ब्याज में छूट मिलेगी। मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए कृषि अधोसंरचना फंड स्थापित किया जा रहा है। इस फंड में सात हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इतनी बड़ी राशि के फंड से कृषि से जुड़ी संस्थाओं को रियायती दामों पर कर्ज दिया जाएगा। इन संस्थाओं, समितियों और समूहों को दो करोड़ रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। इतना ही नहीं, वार्षिक ब्याज दर में राज्य सरकार तीन प्रतिशत तक की छूट भी देगी।

अब किसान होंगे उद्यमी

राज्य सरकार की योजना है कि कृषि अधोसंरचना निधि योजना को मिशन मोड में संचालित किया जाए। इस योजना के फंड से किसानों को उद्यमी बनाने का प्रयास किया जाएगा। यही वजह है कि किसानों को उद्यमी बनाने के लिए नई व्यवस्था विकसित की जा रही है। जिससे किसानों को उद्यमी बनने में मदद मिल सके। इसके लिए प्राथमिक कृषि साख समितियों के साथ उत्पादक समूह, स्व-सहायता समूह, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप और बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के साथ ही केंद्रीय राज्य एजेंसियां या सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना को कर्ज लेने के लिए पात्रता होगी। ऐसी इन सभी पात्र संस्थाओं को तीन प्रतिशत ब्याज पर छूट अगले सात वर्ष की अवधि के लिए मिल सकेगी।

प्रोसेसिंग यूनिट भी होगी

मध्यप्रदेश में जिस हिसाब से उत्पादकता है उस अनुपात में सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था फिलहाल नहीं है। इस कारण किसानों को उपज के बेहतर दाम की आस होल्ड नहीं किया जा सकता और उन्हें औने-पौने दाम पर ही अपनी फसल को बेचना पड़ता है। यही वजह है कि उन्हें ज्यादा फायदा नहीं होता है। इस कारण खेती को लाभ का धंधा बनाने की मुहिम को झटका लगता है। इसलिए अब प्रदेश में एक जिला एक पहचान के तहत विभिन्न जिलों में सब्जियों और फलों के उत्पादन की अधिकता का लाभ लेते हुए प्रोसेसिंग यूनिट विकसित करने की योजना बनाई गई है। इससे किसानों को ही फायदा होगा।

भंडारण व्यवस्था होगी पुख्ता

वर्तमान में उत्पादन अधिक हो जाने से उत्पाद की कीमत कम हो जाने में किसान लाभान्वित नहीं हो पाता। उद्यानिकी विभाग की ओर से एक पैक हाउस, कोल्ड रूम, इंटीग्रेटेड हाउस, इंटीग्रेटेड कोल्ड चैन सप्लाई, मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट, सेटिंग एंड ग्रेडिंग के प्रकरण तैयार किए जा रहे हैं। इस संबंध में आत्मनिर्भर वेबीनार में रोडमैप बनाने के लिए हुए विचार विमर्श में ठोस सुझाव मिले थे। अब इन्हें क्रियान्वित किया जाएगा।

सुझावों पर होगा अमल

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए बनाए गए रोडमैप में कई ठोस सुझाव मिले हैं। सुझावों में कहा गया है कि सिर्फ सब्सिडी आदि से किसानों का कल्याण संभव नहीं है, बल्कि लंबी अवधि की प्लानिंग तैयार कर बिचौलियों से उत्पादकों को बचाते हुए उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवाए जाना चाहिए। यही बजह है कि अब मध्यप्रदेश में कृषि अधोसंरचना फंड से जुड़े कामों को मिशन मोड पर कराने की तैयारी की गई है।

तेजी से बढ़ेगी आय

कृषि अधोसंरचना फंड के तहत ही प्रदेश में उन्नत सीड ग्रेडिंग प्लांट, वेक्यूम व्हीट पैकिंग यूनिट, वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज की चैन विकसित होगी। केंद्र सरकार ने अपने फंड में एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब इन्हीं सुझावों को आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए तैयार किए गए रोड मैप में शामिल किया गया है जिससे मध्यप्रदेश में किसानों की आय में तेजी से बढ़ोतरी हो सके।

समितियां गठित

मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि, सहकारिता और उद्यानिकी विभाग की गतिविधियां शुरू हो चुकी है। इसके लिए कृषि विभाग की तरफ से राज्य स्तरीय निगरानी समिति और जिला स्तरीय निगरानी समितियों के गठन, कृषक उत्पादक समूहों को आंदोलन के रूप में विकसित करने का कार्यक म बनाया गया है। हर विकासखंड से योजना के तहत कम से कम दो प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

300 समितियां चिन्हित

सहकारिता विभाग की तरफ से भारत सरकार के उपक्रम नाबार्ड, एनसीडीसी के अधिकारियों को शामिल करते हुए सहकारिता विभाग, अपेक्स बैंक और मार्कफेड के अधिकारियों की कमेटियों का गठन किया जा चुका है। निर्धारित मापदंडों के अनुसार लगभग ढाई सौ से ज्यादा जिला स्तरीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और 50 से ज्यादा विपणन समितियों को चिन्हित कर लिया गया है।

इंदौर के खरीदी केंद्रों पर 100 हम्माल बीमार, खरीदी केंद्रों पर हम्मालों की पड़ रही कमी

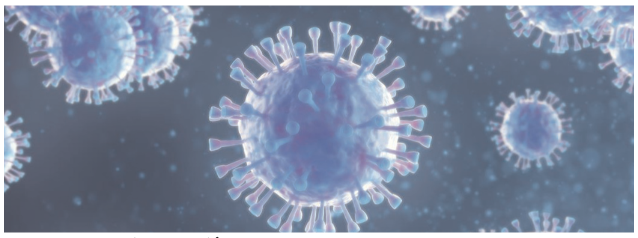

गेहूं खरीदी केंद्रों तक पहुंचा कोरोना अब तक 103 कर्मचारियों की मौत

संवाददता, इंदौर

कोरोना महामारी के बढ़ते दायरे के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की सरकारी खरीदी में भी कई मुश्किलें आ रही हैं। इंदौर जिले के करीब 50 खरीदी केंद्रों पर कमचारी संक्रमित हो चुके हैं। प्रदेश स्तर पर देखा जाए तो अब तक करीब 103 से ज्यादा कर्मचारियों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जो गेहूं खरीदी के काम में लगे थे। इंदौर संभाग में करीब 25 कर्मचारियों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। इनमें सेवा सहकारी संस्थाओं, सहकारी बैंक और मार्कफेड के कर्मचारी शामिल हैं। इंदौर के विभिन्न खरीदी केंद्रों पर 100 हम्माल बीमार हैं। इनमें बिहार, खंडवा, खरगोन, धार, मक्सी आदि के हम्माल शामिल हैं। कोरोना के डर से कुछ केंद्रों पर हम्मालों ने काम करना बंद कर दिया है। फिलहाल अधिकारी और केंद्र प्रभारी किसी तरह काम चला रहे हैं, लेकिन खरीदी में लगातार अड़चन आती जा रही है।

बिहार-खंडवा के हम्माल

हर साल गेहूं खरीदी के दौरान बिहार और खंडवा से अधिक हम्मालों को बुलाया जाता है। इस बार भी हम्माल आए हुए तो हैं, लेकिन अब गांवों में भी कोरोना संक्रमण फैलने से हम्माल भी डरने लगे हैं। कुछ हम्माल काम से पीछे हट गए हैं और अपने गांव चले गए हैं। इस कारण खरीदी केंद्रों पर हम्मालों की कमी पड़ती जा रही है।

बीमारों को भेजा वापस

सहकारिता उपायुक्त एमएल गजभिये ने बताया कि हम्मालों की समस्या तो आ रही है, लेकिन खरीदी न रुके इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। मप्र सहकारी विपणन संघ के क्षेत्रीय संभागीय प्रबंधक अर्पित तिवारी का कहना है कि बीमार होने के कारण खंडवा के 45 हम्मालों को वापस भेजना पड़ा। उनकी जगह दूसरे हम्मालों को लाया गया है।

देश में महक रहा मध्य प्रदेश का धनिया

बिहार में बंगाल नहीं, मप्र के धनिया की बढ़ी डिमांड, गुना जिले की कुंभराज मंडी से की जा रही आपूर्ति

संवाददाता, भोपाल

खेती-किसानी में नवाचारों के लिए दुनियाभर में चर्चित मप्र एक फिर अपनी जायकेदार खेती के चलते सुर्खियां बटोर रहा है। गौरतलब है कि प्राचीन काल से ही विश्व में भारत देश को मसालों की भूमि के नाम से जाना जाता है। धनिया के बीज एवं पत्तियां भोजन को सुगंधित एवं स्वादिष्ट बनाने के काम आते हैं। धनिया बीज में बहुत अधिक औषधीय गुण होने के कारण कुलिनरी के रूप में, कार्मिनेटीव और डायरेटिक के रूप में उपयोग में आते हैं। धनिया अम्बेली फेरी या गाजर कुल का एक वर्षीय मसाला फसल है। इसका हरा धनिया सिलेंट्रो या चाइनीज पर्सले कहलाता है। मध्यप्रदेश में धनिया की खेती 1,16,607 हेक्टेयर में होती है, जिससे लगभग 1,84,702 टन उत्पादन प्राप्त होता है। औसत उपज 428 किग्रा प्रति हेक्टेयर है। मप्र के गुना, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़, विदिशा, छिंदवाडा आदि प्रमुख धनिया उत्पादक जिले हैं। हालांकि राज्यों की बात की जाए तो धनिया की खेती पंजाब, गुजरात, राजस्थान, बिहार, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कनार्टक और उत्तर प्रदेश में भी की जाती है। दरअसल, मध्यप्रदेश के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। यह उपलब्धि मिली है धनिया की खेती से। इस साल बिहार पूरी तरह से धनिया के लिए मध्यप्रदेश पर निर्भर हो गया है। अब बिहार के पकवानों में पूरी तरह से मप्र के धनिया का जायका मिलेगा।

बंगाल से आगे निकला एमपी

बिहार में धनिया की पूरी आपूर्ति प्रदेश के गुना जिले की कुंभराज की मंडी से की जा रही है। अभी तक बिहार में पश्चिम बंगाल का धनिया आता था, लेकिन मप्र को यह मौका मिला है, पश्चिम बंगाल में इस बार धनिया की फसल अत्याधिक बारिश की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो जाने की वजह से। इसके पहले तक बिहार पश्चिम बंगाल से ही धनिया की खरीदी करता था। मध्य प्रदेश से बिहार को अधिकांश धनिया की आपूर्ति कुंभराज मंडी से की जा रही है। उल्लेखनीय है कि मप्र में गुना जिले का कुंभराज का इलाका धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है।

- कुंभराज मंडी से 12500 बोरी धनिया बिहार भेजा
- चार प्रमुख किस्मः ग्रीन, बादामी, स्कूटर और ईगल
- मध्यप्रदेश में अभी धनिया की खेती 1,16,607 हेक्टेयर में हो रही
- उत्पादक जिले: गुना, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़, विदिशा और छिंदवाड़ा

12500 बोरी धनिया भेजा बिहार

कुंभराज मंडी का नाम एशिया के उन मंडियों में शामिल है, जहां पर सर्वाधिक धनिया का कारोबार होता है। अब तक कुंभराज मंडी से 12500 बोरी धनिया बिहार भेजा जा चुका है। कुंभराज मंडी की देश विदेश में पहचान धनिया के उत्पादन और गुणवत्ता के साथ ही कम दामों की वजह से है। क्षेत्र में मुख्य रूप से चार किस्म के धनिया की पैदावार की जाती है। इसमें ग्रीन, बादामी, स्कूटर तथा ईगल ब्रांड का धनिया शामिल है। यह चारों किस्म पूरे देश में बेहद पसंद की जाती हैं, कमी की वजह से इसकी मांग देश में बनी रहती है।

विदेशों में भी निर्यात होता धनिया

कुंभराज में पैदा होने वाले धनिया की मांग देश-विदेश में बड़े पैमाने में होने की वजह से उसका निर्यात भी खूब किया जाता है। यहां का धनिया मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में निर्यात किया जाता है। इस मंडी की खास बात यह है कि यहां पर राजस्थान के बारां, छबड़ा, मप्र के शिवपुरी, गुना, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर आदि जिलों से भी धनिया विक्रय के लिए किसान लेकर आते हैं।

डेढ़ लाख बोरी का मिला ऑर्डर

अभी गुना से बिहार के पटना, धनबाद, मुगलसराय सहित कई क्षेत्रों में धनिया को भेजा जा रहा है। राजगढ़ मंडी से भी धनिया का बिहार निर्यात किया जा रहा है। यह दोनों ही इलाके प्रदेश के सबसे अधिक धनिया के उत्पादक हैं। बिहार धनिया के आयात के लिए गुजरात का भी विकल्प था, लेकिन मप्र से बिहार का भाड़ा कम होने से यह सस्ता पड़ता है। इस साल कुंभराज से ही बिहार को डेढ़ लाख बोरी धनिया निर्यात किया जाना है। जिसका ऑर्डर मप्र को मिला है।

उपयुक्त उन्नत किस्म

किस्म	उपज क्षमता (क्विं./हे.)
हिसार सुगंध	19-20
आरसीआर 41	9-10
कुंभराज	14-15
आरसीआर 435	11-12
आरसीआर 436	11-12
आरसीआर 446	12-13
जीसी 2	15-16
आरसीआर 684	13-14
पंत हरितमा	15-20
सिम्पो एस 33	18-20
जेडी-1	15-16
एसीआर 1	13-14
सीएस 6	12-14
जेडी-1	15-16
आरसीआर 480	13-14
आरसीआर 728	14-15

धनिया से मिलने वाले तत्व

तत्व	मात्रा
प्रोटीन	14.1 ग्राम
वसा	16.1 ग्राम
रेशा	36.2 ग्राम
काबोर्हाइड्रेट	21.6 ग्राम
थायमिन	0.22 मिग्रा
राइबोफ्लेविन	035 मिग्रा
निकोटिनिक अम्ल	1.10 मिग्रा.
विटामिन ए	1570.0 आईयू

धनिया का उपयोग और महत्व

धनिया एक बहुमूल्य बहुउपयोगी मसाले वाली आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी फसल है। धनिया के बीज एवं पत्तियां भोजन को सुगंधित एवं स्वादिष्ट बनाने के काम आते हैं। धनिया बीज में बहुत अधिक औषधीय गुण होने के कारण कुलिनरी के रूप में, कार्मिनेटीव और डायरेटिक के रूप में उपयोग में आते हैं। भारत धनिया का प्रमुख निर्यातक देश है। धनिया के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है।

जलवायु: शुष्क व ठंडा मौसम अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनुकूल होता है। बीजों के अंकुरण के लिए 25 से 26 से.ग्रे. तापमान अच्छा होता है। धनिया शीतोष्ण जलवायु की फसल होने के कारण फूल एवं दाना बनने की अवस्था पर पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। धनिया को पाले से बहुत नुकसान होता है। धनिया बीज की उच्च गुणवत्ता एवं अधिक वाष्पशील तेल के लिए ठंडी जलवायु, अधिक समय के लिए तेज धूप, समुद्र से अधिक ऊंचाई एवं ऊंचहन भूमि की आवश्यकता होती है।

भूमि और उसकी तैयारी

धनिया की सिंचित फसल के लिए अच्छा जल निकास वाली अच्छी दोमट भूमि सबसे अधिक उपयुक्त होती है। असिंचित फसल के लिए काली भारी भूमि अच्छी होती है। धनिया क्षारीय एवं लवणीय भूमि को सहन नहीं करता है। अच्छे जल निकास एवं उर्वरा शक्ति वाली दोमट या मटियार दोमट भूमि उपयुक्त होती है। मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए। सिंचित क्षेत्र में अगर जुताई के समय भूमि में पर्याप्त जल न हो तो भूमि की तैयारी पलेवा देकर करनी चाहिए। जिससे जमीन में जुताई के समय ढेले भी नहीं बनेंगे। खरपतवार के बीज अंकुरित होने के बाद जुताई के समय नष्ट हो जाएंगे। बारानी फसल के लिए खरीफ फसल की कटाई के बाद दो बार आड़ी-खड़ी जुताई करके तुरन्त पाटा लगा देना चाहिए।

पशु जन्य खाद्य उत्पादों में रासायनिक अवशेष: जन स्वास्थ्य का एक मुद्दा

डॉ. विपिन कुमार गुप्ता और डॉ. आरएस तायड़े, प्रभारी अधिकारी, पशुपालन महाविद्यालय, महू

आज के युग में पशु जन्य खाद्य पदार्थों का हमारे दैनिक जीवन मे अत्यधिक महत्व है। पशु उत्पाद हमारे खान-पान का एक नियमित एवं विशेष भाग हैं। यह उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेड, विटामिन्स और मिनरल के उत्कृष्ट स्त्रोत होते हैं, जो कि मानव की पोषकीय, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, रुग्णीय, नैदानिक इत्यादि जरुरतों की पूर्ति में सहायक होते हैं।

आज के युग में पशु जन्य खाद्य पदार्थों का हमारे दैनिक जीवन मे अत्यधिक महत्व है। पशु उत्पाद हमारे खान-पान का एक नियमित एवं विशेष भाग हैं। यह उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेड, विटामिन्स और मिनरल के उत्कृष्ट स्त्रोत होते हैं, जो कि मानव की पोषकीय, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, रुग्णीय, नैदानिक इत्यादि जरुरतों की पूर्ति में सहायक होते हैं। एक कथन के अनुसार मनुष्य की दैनिक आय बढ़ने पर, उसकी पशु जन्य खाद्य की दैनिक खपत भी बढ़ जाती है। वह उच्च गुणवत्ता युक्त, पौष्टिक आहार लेने के लिए पशु उत्पादों को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल करने लगता है। विश्वभर में कृषि एवं पशुपालन की विभिन्न अवस्थाओं में कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण आज रासायनिक अवशेष की विशिष्ट समस्या पशु जन्य खाद्य प्रदार्थों में उत्पन्न हो रही है। जिसका मानव शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव होता है। प्रस्तुत लेख में इसी समस्या को विस्तार से वर्णित किया गया है।

पशु उत्पाद: पशुओं से प्राप्त उत्पाद, जो हमें पशुओं के शरीर भाग एवं उनके स्त्रावण से प्राप्त होते हैं, उन्हें पशु उत्पाद कहते हैं, जैसे कि दूध, वह स्त्रावण है जो दुधारू पशुओं (गाय, भैस, बकरी आदि) की दुग्ध ग्रंथियों से मिलता है, जिसके पोषक तत्वों का उपयोग मनुष्य अपने भोजन में करता है। ऐसे ही मांस, जो कि पशुओं (भैंस, शूकर, बकरी, भेड़, मुर्गों आदि) को मारकर और उनके शरीर के भागों को , मनुष्य भोजन में उपयोग करता है। ऐसे ही अंडा, जो कि पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों द्वारा दिया जाता है। दूध, मांस, अंडे एवं अन्य पशु जन्य खाद्य उत्पादों का उपयोग मनुष्य अपनी भोजन की आवश्यकता, शारीरिक पोषकता एंव वृद्धि के लिए करता है, ये उत्पाद सुपाच्य होने के साथ-साथ विभिन्न आयुवर्ग एवं अवस्थाओं वाले मनुष्यों के लिए उपयुक्त आहार होते हैं। ये सभी पशु उत्पाद के अंतर्गत आते हैं।

रसायन: यह पशुओं के लालन-पालन एवं उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में प्रयोग होते हैं, जैसे कि प्रति जैविक/पशु के इलाज की दवाइयां, कीटनाशक, मृदा उर्वरक, पशु उत्पाद, को व पशु भोजन को संरक्षित करने के स्तर पर, उसे खराब होने से बचाने के लिए, बधंक गुण को बढ़ाने लिए, स्वादिष्टता, पोषकता को बढ़ाने के लिए, इसके अंतर्गत प्रति आक्सीकारक, इमल्सीफायर, खाद्यरंजक, कृत्रिम मधुकारक/ कर्मक, परिरक्षक, सड़न आदि से बचाने वाले यौगिक इत्यादि रसायन होते हैं।

कीटनाशक: वह पदार्थ जो कि कीटों को मारने, उनके आकर्षण को रोकने के लिए, साथ ही प्रतिकर्षण के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। सामान्यत: यह पशुओं से बाह्य परजीवियों को हटाने व मारने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।

रासायनिक कीटनाशकों के प्रकार: आर्गेनो क्लोरीन रसायन, डीडीटी, एचसीएच, डाइएल्ड्रीन, क्लोरडेन, मेथोक्सीक्लोर इत्यादि। आर्गेनो फास्फोरस रसायन, माला-थियॉन, फेन्थीयांन, क्लोरपाइरीफॉस इत्यादि। कार्बोमेट रसायन, प्रोवोक्जयूर, कार्बारिल इत्यादि।

स्त्रोत: पशुओं के शरीर में बाह्य त्वचा पर संचित/संग्रहित रसायन जैसे डीडीटी, एचसीएच धीरे-धीरे वाष्पित होकर त्वचा छिद्रों के द्वारा पशुओं के शरीर में अवशोषित हो जाते हैं। उच्च अवशेष सीमा से नीचे यह रसायन शरीर में प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव नहीं दिखाते हैं, लेकिन शरीर में उच्च अवशेष सीमा से ऊपर मात्रा होने पर प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव दिखाई देने लगते हैं।

पशु उत्पादों में कीटनाशक अवशेष: कीटनाशक अधिक मात्रा में वसा पदार्थों से सजातियता रखते हैं और यह जैविक रूप से सचिंत होने लगते हैं। यह जहरीले कीटनाशक,पशुओं के शरीर में वसा उतकों से पशु उत्पादों जैसे दुध, मॉस, अंडों में पहुंचकर इन्हें दूषित करते हैं। विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों में ओर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह धीरे-धीरे टूटती है और इसकी स्थिरता वातावरण में ज्यादा होती है। मध्यम तरीके की रासायनिक दूषिता मानव शरीर में सिरदर्द, बैचेनी, दस्त, पेट खराबी तथा शरीर कें कमजोर भागों में उतेजितता बढ़ाती है। ओर्गेनो फास्पोरस कीटनाशक, फास्फोरिक अम्ल से उत्पादित होता है जिसमें फास्फोरस, कार्बनहाइड्रोजन, आक्सीजन और सल्फर होती है। यह मानव शरीर में टूटकर कुछ विषैली पदार्थ बनाता है जो कि बहुआयामी विषैले होते हैं। यह कोलिनएस्टरेज प्रतिबंधक होते हैं। कोलिन-एस्टरेज एंजाइम मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का उपयोगी कारक है। कीटनाशकों की कोलिन एस्टरेज रोधक क्रिया के कारण तांत्रिक संकेत शरीर के विभिन्न भागों में नहीं पहुंच पाते हैं। इसके लक्षण मनुष्य शरीर में अधिक मात्रा में सलाईवा (लार) निकालना, श्वसन में कठिनाई, आंखों में धुंधलापन, कमजोरी, मॉसपेशियों की ऐठन, उबकाई, उल्टी, तेज या धीमी हद्रयगति, सिरदर्द, चक्कर आना इत्यादि है। यह पूरी तरह से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।

कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग: फसलों में कीटनाशकों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। किसानों के द्वारा कीटनाशकों की मात्रा का प्रयोग निर्धारित मात्रा से अधिक किए जाने के परिणाम स्वरूप यह कीटनाशक खाद्य श्रृंखला में प्रविष्ट कर पशु जन्म खाद्य पदार्थों में अवशेष के रूप में आने लगते हैं।

कीटनाशकों के अनुपातहीन रूप से प्रयोग: कीटनाशकों का भारत में अनुपातहीन रूप से प्रयोग किया जा रहा है। कीटनाशकों के अवशेषों की मात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न-भिन्न पाई गई है। किसानों द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कीटनाशकों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को आर्थिक एंव शारिरिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों में जागरूकता की कमी के कारण यह हो रहा है इसलिए उच्च कीटनाशक खपत वाले राज्यों के खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों के अवशेष अधिक पाए गए हैं। साथ ही रासयनिक अवशेष जन्य स्वास्श्य समस्याएं भी इन राज्यों में अधिक हैं।

कोराना टीके का इंतजाम

यह अब स्पष्ट हो गया है कि कोविड नियंत्रण में व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम का महत्व सबसे ज्यादा है। वैज्ञानिक कह रहे हैं, अगर किसी देश में लगभग सत्तर प्रतिशत जनसंख्या को टीका लग जाए, तो यह लगभग तय है कि उस देश से कोविड का उन्मूलन हो जाएगा। कई देश इस दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ देश जल्दी ही पूरी जनसंख्या को टीका लगाने का लक्ष्य पा लेंगे। ग्रेट ब्रिटेन ने तो लोगों को तीसरी खुराक देने की योजना बनाना भी शुरू कर दिया है। कई साधनहीन देश जरूर इस दौड़ में पिछड़ रहे हैं, क्योंकि साधन संपन्न देशों ने पहले अपने नागरिकों को टीके मुहैया कराने को प्राथमिकता दी है। भारत में हालांकि खुद दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाली संस्थाएं हैं, लेकिन इस दौड़ में यह काफी पिछड़ गया है। इसकी वजह यह रही कि हमारी सरकार ने वैक्सीन की जरूरत के मुताबिक योजना बनाकर पहले ऑर्डर नहीं दिए। अब जब भारत में कोरोना की ताजा लहर भयावह रूप ले चुकी है, तब तेजी से टीके लगाने की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। सरकार ने यह एक अच्छा काम किया है कि दुनिया के कई टीकों को भारत में लगाने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी सरकार ने कोरोना की गंभीर स्थिति के मद्देनजर इस दौरान वैक्सीन को बौद्धिक संपदा अधिकार के दायरे से बाहर रखने की बात कही है। इन वजहों से भारत में टीकाकरण की रफ्तार तेज होगी, लेकिन इन सबका असर जमीन पर दिखने में अभी कुछ वक्त लगेगा। टीकों की भारत में उपलब्धता आसान करने के लिए सरकार एक और कदम उठा सकती है कि टीका निर्माताओं को टीकों के संभावित दुष्प्रभावों के लिए कानूनी बाध्यता से मुक्त कर दे। टीका निर्माताओं की हिचकिचाहट का एक बड़ा कारण इससे खत्म हो जाएगा। अगर किसी पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, तो उसके लिए सरकार अपने स्तर पर नुकसान भरपाई और मुआवजे का इंतजाम कर सकती है। इसके लिए सरकार चाहे, तो किसी बीमा कंपनी से करार कर सकती है। इस मामले में खतरे या फिक्र की बात इसलिए भी नहीं है कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों को टीके लग चुके हैं और ऐसी कोई खबर नहीं आई है, जिससे किसी गंभीर खतरे का आभास हो। जाहिर है, कोई भी दवा या वैक्सीन शत-प्रतिशत निरापद नहीं होती, लेकिन अभी जो वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, उनसे दुष्प्रभावों की संख्या नगण्य है। इसलिए वैक्सीन की सुरक्षा की गारंटी सरकार ले, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा ।

भारत जैसे देश में इस बात का ज्यादा महत्व इसलिए है कि यहां सरकार की विशेष विश्वसनीयता होती है। अगर लोग यह जानेंगे कि सरकार सुरक्षा की गारंटी ले रही है और किसी आकस्मिक मुश्किल के वक्त वह हमारी मदद करेगी, तो वैक्सीन के प्रति अगर कुछ हिचक है भी, तो वह कम होगी। वैसे भी आम भारतीयों के लिए किसी कंपनी के बजाय अपनी सरकार से शिकायत करना ज्यादा आसान होगा। इस तरह, यह स्थिति वैक्सीन निर्माताओं के लिए भी ठीक होगी और हमारे नागरिकों के लिए भी। यह देखा जा रहा है कि कोविड राहत से जुड़े कई मामलों में बहुत छोटे-छोटे तकनीकी या प्रशासनिक मुद्दों की वजह से देर हो रही है, जो कि ऐसी आपात स्थिति में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।

आज देश की जनता की मांग-कोरोना महामारी से मुक्त हो हमारा भारत

विवेक काटजू

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम नए सिरे से यह संकेत देने वाले रहे कि कांग्रेस मुक्त भारत के हालात बन रहे हैं, लेकिन आज देश की जनता की सबसे बड़ी मांग कोरोना मुक्त भारत की है। लोग फिलहाल केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ समूचे राजनीतिक वर्ग से यह चाहते हैं कि वे दलगत भावना और वैचारिक आग्रह से ऊपर उठकर काम करें। यह मांग इस कारण से बहुत स्वाभाविक है कि देश विभाजन के बाद अपने सबसे मुश्किल दौर से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर को उचित ही तूफान की संज्ञा दी। यह सच में एक तूफान ही है, जो लोगों की जान पर आफत बनकर टूटा है। तमाम परिवारों ने अस्पतालों में बेड या आक्सीजन न मिलने और कई मामलों में उपचार के अभाव में अपने प्रियजनों को खो दिया। इससे आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। कोरोना संकट लोगों के स्वास्थ्य पर आघात करने के साथ ही आर्थिक दुष्प्रभाव पैदा कर रहा है, जिसके सामाजिक एवं राजनीतिक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। इन दुष्प्रभावों को दुनिया भी देख रही है। नंदीग्राम की हार भले ही ममता बनर्जी के लिए व्यक्तिगत शर्मिंदगी का सबब बनी हो, लेकिन उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पूरे बंगाल पर छा गई। कोई भी निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक इसे नहीं झुठला सकता कि ममता ने अकेले अपने दम पर भाजपा का सामना किया। पीएम मोदी से लेकर भाजपा के तमाम दिग्गजों की कोई भी रणनीति ममता के तीसरे कार्यकाल में बाधा नहीं डाल सकी।

हालांकि राज्य में भाजपा ने अपनी सीटों में भारी इजाफा किया। बंगाल में अब उसके 77 विधायक हो गए हैं। वहीं असम की विषम परिस्थितियों के बावजूद भाजपा राज्य की सत्ता बचाने में सफल रही तो पुडुचेरी में भी उसका गठबंधन जीत गया। उधर, वाम मोर्चे ने केरल की परंपरा को पलटकर सत्ता में वापसी की तो दशक भर बाद द्रमुक तमिलनाडु की सत्ता में लौटी। अब इन सभी विजेताओं सहित शेष भारतीय राजनीतिक वर्ग को महामारी से मुकाबले की संपूर्ण प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी होगी। उनके पास गंवाने के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है। यह अच्छा लगा कि अपने विजयी भाषणों में नेताओं ने महामारी से लड़ने को अपनी प्राथमिकता बताया।

भारतीय राजनीतिक वर्ग के लिए यह ऐसा समय है कि वह जनता को यह संदेश दें कि महामारी जैसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए वे अपने मतभेद भुलाकर एकजुट होकर काम करने में सक्षम हैं। इस मिशन की मशाल प्रधानमंत्री मोदी को ही थामनी पड़ेगी, जो निर्विवाद रूप से देश की सबसे बड़ी राजनीतिक हस्ती हैं और लोगों पर उनका गहरा प्रभाव भी है। यदि प्रधानमंत्री कोई पहल करते हैं तो अन्य नेताओं की भी यह उतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वे उस पहल पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। जिन नेताओं और प्रशासनिक एवं तकनीकी दिग्गजों से प्रधानमंत्री संपर्क साधें तो उन्हें अपनी क्षमताओं के दायरे में जनसेवा करने में कोई हिचक नहीं दिखानी चाहिए। इससे विश्व में यही संदेश जाएगा कि जब भारत किसी भीषण संकट का सामना करता है तो उससे निपटने के लिए उसकी राजनीतिक और प्रशासनिक बिरादरी में एकजुट होकर उसका समाधान करने की क्षमता आ जाती है।

कहने का अर्थ यह नहीं कि मौजूदा सरकारें और अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे नेता महामारी के दौरान अपनी नीतियों एवं गतिविधियों को लेकर जनता के प्रति जवाबदेह नहीं। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने गलत ही किया, लेकिन उन्हें अपनी नीतियों एवं कदमों को लेकर स्पष्ट होना होगा। यह भारतीय लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है। यदि कोई व्यक्ति या वर्ग महामारी के दौर में जवाब मांग रहा है तो उसे राष्ट्रविरोधी या महामारी के खिलाफ मुहिम को कमजोर करने वाला नहीं करार दिया जा सकता। साथ ही यह ध्यान रखा जाए कि सवाल उठाने की मंशा किसी निहित स्वार्थ से प्रेरित न हो, जो स्वास्थ्य कर्मियों जैसे उस वर्ग के मनोबल पर आघात करे, जो इस मुश्किल वक्त में मोर्चे पर सबसे आगे डटा हुआ है।

इस समय पूरी दुनिया की नजरें भारत पर लगी हुई हैं। जहां कुछ देशों ने भारत के साथ सहानुभूति जताने के साथ मदद भी पहुंचाई, वहीं अंतरराष्ट्रीय मीडिया के कुछ वर्गों ने महामारी की दूसरी लहर से निपटने में मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है। हालात ऐसे बन गए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को भारतीय राजदूतों एवं उच्चायुक्तों के साथ एक वर्चुअल कांफ्रेंस तक करनी पड़ी। उसमें जयशंकर ने राजनयिकों से कहा कि वे अंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाले अखबारों और चैनलों पर भारत को लेकर बनाए जा रहे खराब विमर्श की काट करें। इसके बावजूद हकीकत यही है कि विमर्श की धारा को मोड़ना मुश्किल है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं की किल्लत को नकारा नहीं जा सकता।

आईसर के वैज्ञानिकों को एक साल बाद मिली सफलता

मध्यप्रदेश में अच्छे बीज अंकुरण के जीन की खोज

जीन वर्ण के अनुरूप तैयार करने में भी होगा मददगार साबित

संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार ही नहीं, हमारे कृषि वैज्ञानिक भी जुटे हैं। ताकि किसानों को कम लागत में अच्छा उत्पादन मिले और उनकी आया भी बढ़े। ताकि किसान आत्मनिर्भर हो सकें। हाल ही में एक शोध में मिली सफलता से किसानों की सबसे बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। यह चिंता है अच्छे बीज की बोवनी के बाद भी उनमें कम मात्रा में अंकुरण के साथ ही अच्छी फसल न होना। इसके कई कारण रहते हैं। लेकिन अब ऐसे मामलों में किसानों को चिंता करने की जरुरत नहीं रहेगी। दरअसल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आईसर) भोपाल के वैज्ञानिक ने हाल ही में 1 साल के शोध के बाद पौधों में पाए जाने वाले बीबीएक्स-11 नामक जीन की खोज की है, जो बीज अंकुरण का मुख्य कारक होता है। यही नहीं, यही जीन वर्ण के अनुरूप तैयार करने में भी मददगार रहता है।

अब सोयाबीन पर शोध

आईसर के बायोलॉजिकल साइंस विभाग के वैज्ञानिकों की टीम ने अराबिडोप्सिस (सरसों की प्रजाति) पर इसका लगातार कई फसलों पर भी शोध किया। इसकी वजह है इस पौधे में सर्वाधिक 25000 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। टीम ने इनमें से एक जीन बीबीएक्स-11 की पहचान की है, जो फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करता है। इस जीन से बनने वाले प्रोटीन की मात्रा कम या अधिक होने पर उसका असर उपज पर पड़ता है। खास बात यह है कि यही जीन सोयाबीन धान और गेहूं के पौधे में भी पाया जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा अब सोयाबीन पर इसके प्रभाव को लेकर शोध शुरू कर दिया गया है।

बढ़ जाएगा अंकुरण

बीजों के अंकुरण के कोई भी प्रमाणिक तथ्य नहीं हैं। लेकिन माना जाता है कि औसतन 75 फीसदी तक ही बीज ही अंकुरित होते हैं। ऐसे में यह शोध बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। बीबीएक्स-11 वह जीन है जो बीज मिट्टी के अंदर होता है। यह जीन शत-प्रतिशत अंकुरण के साथ ही पौधे को तेजी से बढ़ने में मदद करता है।

ऐसे किया अध्ययन

शोध में जीन की खोज के बाद पहले बीज को प्लांट ग्रोथ चेंबर में रखा गया। जहां तापमान रोशनी और नमी को संतुलित कर उसके विकास का अध्ययन किया गया। इसके बाद वातावरण के हिसाब से जीन के प्रोटीन की मात्रा को नियंत्रित करके पौधों पर असर देखा गया। सूर्य की रोशनी के सातों रंगों का अलग-अलग प्रयोग कर उसका प्रमाण भी देखा गया।

इस तकनीक से किया शोध

पौधों में प्रोटीन को नियंत्रित करने वाली नोबेल क्रिस्पर कैस तकनीक से इस पर शोध किया गया है। इसके जरिए बीबीएक्स-11 जीन से तैयार होने वाले प्रोटीन की मात्रा को नियंत्रित कर के बीज के अंकुरण और प्रतिकूल वातावरण में पौधे की वृद्धि को दर्ज किया गया। जहां वैज्ञानिकों ने पाया कि जरूरत के हिसाब से प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने पर अच्छे परिणाम आए हैं। यही जीन सोयाबीन, धान और गेहूं में भी होने की वजह से इनकी फसलों को भी नियंत्रित किया जा सकता है।

शोध अमेरिका में हुआ प्रकाशित

डॉक्टर सौरभ दत्ता के इस शोध का प्रकाशन अमेरिका के रिसर्च जर्नल प्लांट फिजियोलॉजी व प्लांट जर्नल में बीते साल के दिसंबर में हो चुका है। इस शोध के लिए हाल ही में उन्हें रामचंद्र नेशनल बायोसाइंस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवॉर्ड के लिए भारत के 10 वैज्ञानिकों का चयन हुआ था।

इनका कहना है

करीब 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक पौधे में हजारों छोटे-छोटे बीज होते हैं। विश्व का पहला पौधा है जिसका सबसे पहले जिनोम सीक्वेंसिंग किया गया। इनका जीवन चक्र दो माह का होने की वजह से इसकी फसलों पर लगातार शोध हो सकता है, जिसकी वजह से इस पौधा को शोध के लिए सबसे अच्छा माना गया है।

डॉ. सौरभ दत्ता,
प्रमुख, बायो लॉजिकल विभाग, आईसर

25 लाख किसानों को अभी तक नहीं मिली सम्मान निधि

संवाददाता, भोपाल

चुनावी साल में किसानों के लिए सरकार योजनाओं की घोषणा तो कर देती है, लेकिन लाभ किसे मिले इसका आंकलन नहीं किया जाता। इस सब में ठगा जाता है तो सिर्फ किसान। जबकि की सत्ता तक पहुंचाने में इनकी भूमिका अहम होती है। दरअसल, मध्यप्रदेश सरकार कितनी गंभीर है, इससे ही समझा जा सकता है कि बीते सात माह से इंतजार कर रहे 24 लाख 69 हजार 580 किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिला है। अब वित्त वर्ष समाप्त होने की वजह से इन किसानों को दो हजार रुपए का नुकसान होना तय है। इतना सब होने के बाद भी अभी तय नहीं है कि किसानों को आखिर कब सम्मान निधि की राशि मिलेगी। गौरतलब है कि बीते साल प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के पहले किसानों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी खजाने की दयनीय हालत होने के बाद भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत किसानों को हर साल चार हजार रुपए मिलने थे।

-जिम्मेदारों की लापरवाही अन्नदाताओं पर पड़ी भारी

-बीते साल मुख्यमंत्री ने ही की थी योजना की घोषणा

पंजियन के नाम पर भी अटकाया

प्रदेश के 28 लाख 14 हजार 858 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पंजीकृत हैं। इन पंजीकृत किसानों की सूची भी प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र को दी गई थी। ऐसे में फिर से प्रदेश में किसानों का नए सिरे से पंजीयन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसके बाद भी प्रदेश के किसानों का नाम अलग से पंजीकृत करने का काम शुरू कर दिया गया।

पैसों की तंगी मुसीबत बनी

सरकार अब तक किसानों को 2000 की पहली किस्त देने के लिए भी पूरी तरह से राशि का इंतजाम नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से ही पंजीयन के नाम पर किसानों को अटका कर रखा गया है। सरकार की हालत इससे ही समझी जा सकती है कि उसे बीते साल लगभग हर माह अपने जरुरी खर्च के लिए कर्ज लेने पर मजबूर होना पड़ा है।

मप्र में 82.14 लाख किसान पंजीकृत

मप्र में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 82 लाख 14 हजार 858 है। इनमें से अब तक 57 लाख 45 हजार 278 किसानों को ही मुख्यमंत्री सम्मान निधि की राशि का भुगतान किया गया है। इस अवधि में किसानों को 1149 करोड़ दिए गए हैं। इसके उलट केन्द्र सरकार द्वारा अब तक प्रदेश के किसानों को पीएम सम्मान निधि के तहत 8476 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

सीएनजी गाड़ियों से उठेगा कचरा नगर निगम के सवा करोड़ बचे

» अच्छी पहलः राजधानी में पर्यावरण नहीं होगा प्रदूषित

» डोर टू डोर शहर से कचरा कलेक्शन करेंगी 25 गाड़ियां

» डीजल वाहनों के मुकाबले सस्ती और प्रदूषण मुक्त भी

संवाददाता, भोपाल

राजधानी भोपाल में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन अब सीएनजी गाड़ियों से होगा। नगर निगम ने पहले चरण में 25 सीएनजी गाड़ियां खरीदी हैं। निगम ने केंद्र के जेम पोर्टल के माध्यम से 7 लाख रुपए में एक गाड़ी के हिसाब से 25 गाड़ियां खरीदी हैं। इस तरह की डीजल व्हीकल करीब 12 लाख में आती है। इस तरह 25 गाड़ियों पर निगम ने एकमुश्त सवा करोड़ बचाए। डीजल की गाड़ियां 12 से 15 का माइलेज देती हैं, जबकि सीएनजी में यह 20 तक होता है। सीएनजी डीजल की तुलना में 10 रुपए लीटर सस्ती हैं। निगम के सहायक यंत्री (वर्कशॉप) चंचलेश गिरहरे के अनुसार एक अनुमान लगाया गया है कि हर महीने कुल 10 लाख रुपए की बचत अलग से होगी। वहीं भोपाल नगर निगम के आयुक्त वीएस चौधरी कोलसानी का दावा है कि शहर के पर्यावरण के साथ नगर निगम के लिए आर्थिक रूप से भी सीएनजी गाड़ियां फायदेमंद हैं। हम 25 गाड़ियों से शुरू कर रहे हैं। जल्द ही इनकी संख्या भी बढ़ाएंगे।

रजिस्ट्रेशन की औपचारिकता बाकी

गाड़ियां भोपाल आ गई हैं और वर्कशॉप परिसर में रखी हुई हैं। इनके रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की प्रक्रिया शेष है। कोरोना संक्रमण के कारण लगे प्रतिबंधों की वजह से इसमें देरी हो सकती है। फिर भी कोशिश है कि इस महीने इन औपचारिकताओं को पूरा करा लिया जाएगा।

▪ 52 जिला ▪ 10 संभाग ▪ 52 जिला पंचायत ▪ 300 से ज्यादा जनपद ▪ 23023 ग्राम पंचायत ▪ 16 कुल नगर निगम ▪ 100 नगर पालिका ▪ 250 से ज्यादा नगर पंचायत

मौजूदा गाड़ियों को भी सीएनजी में बदलेंगे

नगर निगम की मौजूदा गाड़ियों को भी सीएनजी में बदलने पर विचार किया जा रहा है। इस पर आने वाले खर्च और उपलब्ध बजट का हिसाब लगाने के बाद इनके बदलाव पर निर्णय होगा।

आदमपुर छावनी में लग रहा प्लांट

निगम नेहरू नगर स्थित पुलिस पेट्रोल पंप से सीएनजी लेगा। इसके साथ ही आदमपुर छावनी में कचरे से बायो सीएनजी का प्लांट स्थापित हो रहा है। यह प्लांट चालू होने पर निगम को सीएनजी और सस्ती मिल सकती है।

प्रदेश में 16 नगर निगम

मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। पूरा प्रदेश 10 संभागों में बटा है। राज्य में 52 जिला पंचायत, 300 से ज्यादा जनपद पंचायत और 23023 ग्राम पंचायत हैं। राज्य में नगर पालिकाओं में, 16 नगर निगम, 100 से ज्यादा नगर पालिका और 250 से ज्यादा नगर पंचायत शामिल हैं।

अरबों की हो सकती है बचत

प्रदेश में जितनी भी कचरा गाड़ियां हैं, अगर सब को सीएनजी में तब्दील कर दिया जाए तो नगर सरकार की अरबों रुपए की बचत होगी। भोपाल में ही दावा किया जा रहा है कि 25 सीएनजी गाड़ियां आने से हर माह दस लाख की बचत होगी। इससे साफ है कि अन्य शहरों में भी इसी तरह हर माह बचत होगी। यानि अरबों रुपए बचेंगे।

...तब प्रदूषण मुक्त होगा एमपी

धीरे-धीरे महानगरों भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के सरकारी कार्यालयों में उपयोग होने वाले सभी वाहनों को अगर सीएनजी में बदल दिया जाए तो आने वाले समय में मप्र पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। गौरतलब है कि प्रदूषण के मामले में मप्र दिल्ली-एनसीआर बनने की कगार पर पहुंच गया है।

टीकमगढ़ के वैज्ञानिकों ने किसानों को बताए फायदे

ग्रीष्मकालीन जुताई जल संरक्षण में लाभदायक

टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. बीएस किरार ने बताया कि इस समय हमारा देश वैश्विक महामारी कोरोना के रौद्ररूप का सामना कर रहा है। इस कोरोना वायरस की महामारी से बचने के लिए मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार-बार हाथों को धोएं। अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर टीका जरूर लगवाएं। लोग दो गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें। अपने आस-पास सफाई का विशेष ध्यान रखें। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. किरार एवं वैज्ञानिक डॉ. यूएस धाकड़ ने बताया कि गहरी जुताई से जल, वायु और मिटटी में सुधार होता है और मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता बढ़ती है। खेत की कठोर परत को तोड़कर मिट्टी को जड़ों के विकास के अनुकूल बनाने के लिए ग्रीष्म कालीन जुताई लाभदायक होती है। जुताई से खेत में उगे खरपरतवार और फसल अवशेष मिट्टी में दबकर सड़ जाते हैं। इससे मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा बढ़ जाती है। फल स्वरूप मृदा कार्बनिक पदार्थ का अपघटन तीव्र गति से होने के कारण अगली फसल को पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। खेत में ढलान के आर-पार जुताई करने से ढलान की निरंतरता में रुकावट आती है। इससे वर्षा जल से मृदा कटाव नहीं होता।

पिछली फसल के ठूंठो, खरपरतवारों में तथा मृदा सतह के नीचे बहुत से कीट गर्म मौसम में आश्रय लेते हैं। गर्मी की गहरी जुताई में मिट्टी के पलटने से सूर्य की तेज किरणें मृदा में प्रवेश करके इन मृदा जनित कीटों, उनके अंडों, सूंड़ी, प्यूपा को नष्ट कर देती हैं या खुले में आने से पक्षियों द्वारा खाकर नष्ट कर दिए जाते हैं। अगली फसल में इन कीटों द्वारा फसल को कम नुकसान होता है। उनके प्रबंधन पर होने वाले व्यय की बचत होती है। गहरी जुताई से खरपतवार तथा उनकी गांठें उखड़कर ऊपर आ जाती हैं और तेज धूप में सूखकर मर जाते हैं।

मप्र की पहली लैंडफिल साइट ग्वालियर में, लगा 'ग्रहण'

» ग्वालियर में कचरे से खाद बनाने वाला प्लांट अनदेखी से बंद

» नगर निगम कर्मचारी ही नहीं रख सका

» आठ लाख टन कचरा लैंडफिल साइट पर जमा

ग्वालियर। केदारपुर लैंडफिल साइट कचरे के पहाड़ों में तब्दील हो गई है। यहां पर कभी शहर की जनता को कचरे से बिजली, जैविक खाद और ज्वलनशील पदार्थ (केक) बनाने का सपना दिखाया गया था। अब एक पाली में भी रोज कचरे का निपटान नहीं हो पा रहा है। जबकि 27 फरवरी को आयुक्त शिवम वर्मा ने निरीक्षण के दौरान दोनों पालियों में प्लांट को चालू करने के निर्देश दिए थे। यहां पदस्थ जिम्मेदारों का कहना है कि यदि कर्मचारी मिल जाएं तो दोनों पालियों में प्लांट को चलाया जा सकता है। निगम के जानकारों का कहना है कि अभी प्लांट शुरू किया जाए तो कचरे के निपटान में एक साल लग जाएगा। मप्र में सबसे पहली लैंडफिल साइट ग्वालियर में ही बनी थी। उसके बंद होने पर तीन साल पहले एक बार फिर लैंडफिल साइट को तैयार किया गया। इस बार ईको ग्रीन कंपनी (चीन) को जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

42 कर्मचारियों की जरूरत

प्लांट को दो पालियों में चलाने के लिए हेल्पर आदि कर्मचारियों की जरूरत है। इसके लिए 42 कर्मचारियों की जरूरत बताई जा रही है। आयुक्त कार्यालय को प्लान देने के बाद भी उक्त स्टाफ आज तक प्लांट को नहीं मिला। जैसे-तैसे कर कुछ कर्मचारियों को बुलाया भी गया। वे प्लांट के हालात देखकर दूसरे दिन काम पर नहीं आए। प्लांट पर 125 टन के करीब खाद तैयार रखी हुई है। इसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया।

> वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण समस्या आ रही है। निगम वहां पर जल्द ही स्टाफ को नियुक्त करने की प्रक्रिया करेगा। इससे प्लांट को दो पालियों में चलाया जा सकेगा। तब प्लांट में जैविक खाद आदि बनाए जाएंगे।
>
> -शिवम वर्मा, आयुक्त, नगर निगम

सब्जी की पौध से नूराबाद नर्सरी किसानों को बनाएगी आत्मनिर्भर

- उद्यानिकी विभाग ने नूराबाद नर्सरी को विकसित कराने दो विभागों को पैसा जारी किया
- चार साल से उजड़ा पड़ा नेट व पॉली हाउस, भोपाल की कंपनी काम छोड़कर भागी

संवाददाता, मुरैना

उद्यानिकी विभाग की नूराबाद नर्सरी में इस साल के अंत तक हर मौसम में हर सब्जी उपलब्ध कराने वाली पौध तैयार होने लगेगी। इसके लिए नर्सरी में 9 करोड़ 64 लाख रुपए से नेटहाउस व पॉली हाउस के निर्माण किए जाएंगे।

साथ ही पांच जिलों के किसानों की ट्रेनिंग के लिए सेंटर समेत विश्राम गृह का निर्माण कराया जाएगा। 2013 के इस प्रोजेक्ट पर अब फिर से काम शुरू हो रहा है। भोपाल की आर्सेनिक कंपनी 2016 में नूराबाद नर्सरी में पौधे उगाने का काम छोड़कर भाग गई थी जबकि उद्यानिकी विभाग से उस कंपनी का एक साल में एक करोड़ 20 लाख पौध उगाकर देने का अनुबंध था। विधानसभा के उपचुनाव से पहले केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर फिर से इस प्रोजेक्ट के लिए 9 करोड़ 64 लाख रुपए स्वीकृत कराकर लाए, लेकिन दिसंबर 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक इस प्रोजेक्ट पर उद्यानिकी विभाग कोई काम शुरू नहीं करा सका। वहीं उद्यानिकी विभाग के संचालक मनोज अग्रवाल से इंडो-इजरायल नर्सरी प्रोजेक्ट को लेकर कहना था कि नूराबाद नर्सरी में नेट हाउस व पॉली हाउस तैयार करने के लिए विभाग ने एमपी एग्री को पैसा जारी कर दिया है। नूराबाद नर्सरी परिसर में किसानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर समेत किसान विश्राम गृह बनवाने का काम पीआईयू को सौंपा गया है। दोनों संस्थाओं को बजट भी जारी किया जा चुका है। ऐसी उम्मीद है कि 2021 के अंत तक नूराबाद नर्सरी में हर मौसम में हर सब्जी की पौध तैयार होने लगेगी।

दस करोड़ होंगे खर्च

नर्सरी प्रोजेक्ट के माध्यम से उद्यानिकी विभाग छोटे व मध्यम किसानों की आय में बड़ाना चाहता है। इसके लिए मुरैना जिले के नूराबाद में 9.64 करोड़ रुपए की लागत से वातानुकूलित नर्सरी को विकसित कराएगा।

अब तक 6 करोड़ रुपए खर्च

उद्यानिकी विभाग इस प्रोजेक्ट पर अब तक छह करोड़ से अधिक पैसा खर्च कर चुका है। तीन करोड़ से अधिक के काम हाउसिंग बोर्ड ने नर्सरी परिसर में कराए हैं। प्रोजेक्ट 18 करोड़ का है। इसके बाद भी मुरैना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी व दतिया, के किसानों को बेमौसम की सब्जियों की पौध सरकारी रेट 1.48 रुपए पर नहीं मिल पाई।

तीन प्रमुख बातें

एक: बेमौसम की सब्जियां उगाकर किसान उन्हें महानगरों व मॉल में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए किसानों को बेमौसम की सब्जियों की पौध सस्ती रेट पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

दो: नर्सरी से मिलने वाली पौध बाजार की पौध की तुलना में ढाई रुपए प्रति पौध के मान से सस्ती है। इस कारण यदि पौध खराब होकर नष्ट भी जाती है तो किसानों को बड़े नुकसान की स्थिति नहीं बनेगी।

तीन: सब्जियों की पौध कम समय में उत्पादन देने लगती है, इसलिए सब्जी की फसल को कैश क्रॉप भी कहा जाता है। किसान इधर मॉल में बेमौसम की सब्जी बेचे, उधर दूसरे काउंटर से उसे नकद भुगतान की सुविधा मिलती है।

समर्थन मूल्य पर खरीदी में उज्जैन नंबर-2 किसान भी खुश, न मुसीबत और न हंगामा

संवाददाता, उज्जैन

समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में उज्जैन प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा है। खरीदी की शुरुआत 27 मार्च से हुई थी। 40 दिन में 83625 किसानों ने 6.08 लाख टन गेहूं बेचे। जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बताया खरीदी के लिए पहली बार तीन प्रयोग किए थे। 12 महिला स्वयं सहायता समूह, 4 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के अलावा 4 गोदाम संचालकों को भी खरीदी दायित्व दिया था। महिलाओं, किसानों और गोदाम संचालकों ने जीरो एरर यानी कम से कम गलतियों के आधार पर खरीदी का काम जारी रखा। गेहूं की खरीदी 15 मई तक जारी रहेगी।

महिला स्व सहायता समूह ने की खरीदी

बिस्मिल्लाह आजीविका स्व सहायता समूह बेडावन्या सायलो बैग खाचरौद, मां दुर्गा आजीविका स्व सहायता समूह बुरानाबाद खाचरौद, मां भवानी आजीविका स्व सहायता समूह आवलिया घट्टिया, उपकार आजीविका स्व सहायता समूह मीण घट्टिया, श्री शीतला माता आजीविका स्व सहायता समूह बडखेड़ा नजीक खाचरौद, बाबा रामदेव आजीविका स्व सहायता समूह मलोड़ा बड़नगर, राहत आजीविका स्व सहायता समूह झलारिया बड़नगर, शारदा आजीविका स्व सहायता समूह फतेहपुर गुणावद बड़नगर, मां दुर्गा आजीविका स्व सहायता समूह समूह बलेड़ी व भारत माता आजीविका स्व सहायता समूह कल्हा पिपलिया महिदपुर।

किसान कंपनी भी जुटी खरीदी में

किसानों की उपज खरीदने में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को भी भागीदार बनाया है। कड़ाई और सिजावता की खरीदी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चिकली, तालोद कंडारिया में मेसर्स समृद्ध किसान कंपनी तालोद व ढाबला हर्दू में मेसर्स ढाबला कंपनी खरीदी में जुटे हैं।

निजी गोदाम से भी अनुबंध

मां हरसिद्धि वेयर हाउस पिंग्लेश्वर में 2500 टन, मोहित वेयर हाउस, धम्मनी उज्जैन 2000 टन, हाजी वेयर हाउस नलेश्री तराना 3362 टन, श्रीराम वेयर हाउस, हताई नागदा 3319 टन खरीदी के नए केंद्र बनाए हैं।

ऐसे आसान हुई गेहूं खरीदी

कंट्रोल: खरीदी में किसी प्रकार की समस्या होने पर उसके समाधान के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया। इसके फोन नंबर 0734-2526194 पर किसान अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। ओम प्रकाश गुप्ता, उपायुक्त सहकारिता, मोबाइल नंबर-8319810317 को प्रभारी अधिकारी नियंत्रण कक्ष बनाया है। ताकि यहां आने वाले किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही कोरोना गाइड लाइन का भी कड़ाई से पालन कराया जा रहा है।

सुविधा: किसानों को बैठने के लिए टेंट, पीने का पानी की व्यवस्था। अस्थायी शौचालय, फर्स्ट एड बॉक्स, सैनिटाइजर, मास्क, हम्माल तुलावटी, किसानों के हाथ धुलवाने के लिए साबुन, केंद्र पर संस्था प्रबंधक, प्रशासक, केंद्र प्रभारी, सर्वेयर स्वयं उपस्थित रहकर एसएमएस प्राप्त किसानों से खरीदी कराने में जुटे हैं।

गाइड लाइन का पालन: किसान को खरीदी की ऑनलाइन प्रिंट रसीद देकर उनके गंतव्य की ओर भेजा रहा है। केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइड लाइन का पालन कराया जा रहा है। खरीदे गए गेहूं के स्टॉक के स्टेक लगाकर तिरपाल की व्यवस्था की गई है।

निरीक्षण: तौलकांटों, धर्मकांटों का नापतौल विभाग के अफसर नियमित निरीक्षण कर रहे हैं। तौल में गड़बड़ी न हो और मानक अनुसार तौल किया जाए इसका ध्यान रखा जा रहा है। तौलकांटे के परीक्षण के लिए 50 किलो का सत्यापित बाट रखा गया है। रोज सुबह तौल शुरू होने के पहले किसानों के सामने तौलकांटे का 50 किलो के बांट से परीक्षण कर पंचनामा बनाकर रिकॉर्ड रखा जा रहा है।

सत्यापन: केंद्रों के लिए नियुक्त नोडल अफसर रोज केंद्रों पर उपस्थित होकर समस्याओं का निराकरण करने में जुटे हैं। पंजी में रोज उपस्थिति, समय, दिनांक सहित हस्ताक्षर भी कर रहे हैं। जिला विपणन अधिकारी वाहन लगाकर गेहूं का परिवहन कर भंडारण कर रहे हैं।

छतरपुर में सिंचाई के साथ क्षेत्र की पेयजल समस्या होगी दूर

सूखे बुंदेलखंड की पहचान बनेगा सोयाबीन-शरबती गेहूं

संवाददाता, छतरपुर

मप्र के बुंदेलखंड देशभर में सूखे के लिए जाना जाता है। लेकिन अब छतरपुर का सोयाबीन और शरबती गेहूं क्षेत्र की पहचान बनेगा। दरअसल, हाल ही में वेतबा-केन नदी लिंक परियोजना का मप्र और उप्र के बीच विवाद सुलझने से सर्वाधिक फायदा मप्र के अति पिछड़े बुंदेलखंड के छतरपुर जिले को मिलेगा। इससे किसानों को न केवल बेहतर उपज मिलेगी, बल्कि बेरोजगारों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। अब यहां पैदा होने वाला सोयाबीन और शरबती के साथ ही कठिया गेहूं का भी देश में पहचान बनने का रास्ता खुल गया है। गौरतलब है कि उक्त परियोजना को मंजूरी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेई की सरकार में दी गई थी। उस समय इसकी लागत 35 हजार 111 करोड़ अनुमानित की गई थी। इससे मप्र के साथ ही उप्र के एक दर्जन जिलों की तस्वीर बदलने का रास्ता साफ हो गया है।

गेहूं को चाहिए पानी: यहां होने वाले अच्छे किस्म के गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए पांच बार सिंचाई की जरूरत होती है, लेकिन पानी न होने के कारण सिंचाई नहीं हो पाती है। इससे नुकसान होता है। पानी मिलने से शरबती और कठिया गेहूं की भरपूर फसल ली जा सकेगी।

छह बांध भी बनेंगे

इस परियोजना में आधा दर्जन छोटे-बड़े बांध बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसमें सर्वाधिक बड़ा बांध केन नदी के तट पर बिजावर के 4 गांवों समीप 77 मीटर ऊंचा, 19633 वर्ग किमी जलग्रहण क्षमता का होगा। इसमें 2584 एमसीएम पानी भंडारण की क्षमता होगी। इसके अलावा दो बड़े विद्युत प्रोजेक्ट भी होंगे। जिनमें 36 मेगावाट के दो विद्युत प्लांट शामिल हैं।

50 गांव होंगे विकसित

जिले के ढोड़ना, खरिहानी, मैनारी, सुकवाहा, भंवरकुआं, शहपुरा, पलकौवा सहित करीब आधा सैकड़ा गांवों में विकास का रास्ता खुल जाएगा। जिले का बिजावर विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है। यहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार और पेयजल की बड़ी समस्या है। इससे अब छुटकारा मिल जाएगा।

यहां जल संकट: उक्त परियोजना के पूरा होने पर छतरपुर जिले के नौगांव तहसील मुख्यालय के अलावा इस तहसील के कई बड़े गांवों में शामिल अलीपुरा, जोरन, चीरवारी के अलावा राजनगर, गौरिहार, तहसील मुख्यालय, लवकुशनगर के घूर, प्रतापपुरा, रानीपुरा, देवनगर, मड़वारा, धरमपुरा के साथ ही अतनियां, बरायचखेड़ा, बृजपुरा, चंद्रपुरा, गोपालपुरा, कदारी, रामगढ़, रामपुर, पुछी गांवों को पेयजल संकट से भी मुक्ति मिल जाएगी।

मप्र में की गई थी रिकॉर्ड्ड बोवनी

प्रदेश में अनुकूल मौसम को देखते हुए किसानों ने रिकॉर्ड 58.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बोवनी की थी। उम्मीद थी कि तलहन फसल का भी बंपर उत्पादन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मालवा, निमाड़, महाकोशल सहित अन्य क्षेत्रों में 25 फीसद तक फसल प्रभावित हो गई। नरसिंहपुर में 40, दमोह में 10, सिवनी में पांच फीसद तक किसानों का नुकसान हुआ था। वहीं भोपाल के बैरसिया में तो सौ प्रतिशत तक सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई थी। प्रदेश में पिछले साल 141 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोवनी की गई थी।

कहां कितनी की गई थी बोवनी

जिला	रकबा (हेक्टेयर में)
इंदौर	2.15 लाख
उज्जैन	4.90 लाख
रतलाम	2.40 लाख
धार	5. 85 लाख
खंडवा	1.73 लाख
मंदसौर	2.57 लाख
नीमच	1.21 लाख
देवास	3.76 लाख
शाजापुर	2.76 लाख
झाबुआ	59 हजार
बड़वानी	28 हजार
खरगोन	55.5 हजार
बुरहानपुर	18.36 हजार

3.23 लाख हेक्टेयर में होगी सिंचाई

छतरपुर जिले की अधिकांश जमीन बेहद उपजाऊ होने के बाद भी सिंचाई के अभाव में भरपूर पैदावार किसानों को नहीं दे पाती है, लेकिन अब इस परियोजना के चलते जिले के गोरीहार, छतरपुर, लवकुशनगर, नौगांव और राजनगर तहसील क्षेत्र की 3 लाख 23 हजार 350 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा मिल जाएगी।

बढ़ जाएगा उत्पादन

यहां के किसानों का कहना है कि अभी क्षेत्र में सोयाबीन का उत्पादन अधिक होता है, लेकिन सिंचाई सुविधा नहीं होने से भरपूर फसल नहीं ले पाते हैं। साल भर सिंचाई की सुविधा मिलने से सोयाबीन का भरपूर उत्पादन होगा। इससे क्षेत्र में सोयाबीन का उत्पादन बढ़ जाएगा।

कर्मचारी माने, बंद नहीं करेंगे गेहूं खरीद, सहकारिता मंत्री ने दिया आश्वासन

भोपाल। कोरोना के इस संकट काल में जान जोखिम में डालकर गेहूं उपार्जन का काम कर रहे कर्मचारियों को कोरोना योद्धा नहीं मानने से नाराज कर्मचारियों ने प्रस्तावित कलमबंद हड़ताल स्थगित कर दी है। सहकारिता मंत्री डॉ.अरविंद सिंह भदौरिया द्वारा मांग पर विचार करने और मृतक कर्मचारियों के परिजनों की सहायता करने के आश्वासन पर वे मान गए हैं। उधर, विभाग ने सभी जिलों से कोरोना संक्रमित कर्मचारियों की जानकारी बुला ली है। पंचायत सचिव और संविदा कर्मचारी भी कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग कर रहे हैं। मप्र सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बीएस चौहान ने बताया कि कोरोना संक्रमण की इस दूसरी लहर में समितियों के कर्मचारी पूरी ईमानदारी के साथ किसानों का गेहूं खरीदने में जुटे हैं। 103 कर्मचारियों का निधन कोरोना संक्रमित होने के बाद हो चुका है। इन्हें कोरोना योद्धा अब तक घोषित नहीं किया है।

एमपी में 15 जून तक आएगा मानसून, इस बार झमाझम बारिश

भोपाल। देश में रोज तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की बुरी खबर के बीच मौसम विभाग ने एक अच्छी खबर दी है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस साल मानसून निर्धारित समय पर 1 जून को केरल से टकरा जाएगा और देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है। वहीं अगर मौसम विभाग का अनुमान सही रहा तो इस बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित पूरे राज्य में मानसून तय समय-सीमा या उसके आसपास दस्तक दे सकता है। भोपाल में 15 जून के आसपास मानसून के आने की संभावना है। पिछले दो सालों से मानसून ने 20 जून या उसके बाद राजधानी में दस्तक दी है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अपने तय समय से केरल के तटीय क्षेत्र तक पहुंचेगा और किसानों के लिए आगामी फसल वर्ष के शानदार फसल उत्पादन होने की उम्मीद है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून रहेगा सामान्य: चालू सीजन में देश के 75 फीसद भू-भाग में बारिश करने वाला दक्षिण-पश्चिम मानसून इस वर्ष पूरी तरह सामान्य रहेगा। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि देश के 75 फीसद हिस्से में जून से लेकर सितंबर के बीच अच्छी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि जून से सितंबर के बीच सक्रिय रहने वाले मानसून सीजन में कुल 103 फीसद बारिश हो सकती है।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, गोपाल दास बंसल-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
हरदा, राजेन्द्र बिल्लोरे-9425643410
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, संपर्क-9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)